being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Credit rating agencies is one of the approved Non-Banking Financial Services activities where foreign investment are permitted. There is no minimum capitalisation requirement when the foreign equity is within 51%. However, the foreign partners are required to bring in a minimum of $ 5 million for foreign equity exceeding 51% and upto 75%.

(c) There is no such proposal under the consideration of the Government at present.

**Opening more CGHS Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries in Delhi**

2952. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether some requests for opening more Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries, under CGHS in Delhi have been received during 1994, 1995 and upto June, 1996;

(b) if so, the details thereof, locality-wise:

(c) whether Government propose to set up such dispensaries during current year to meet long outstanding demands;

(d) whether Government propose to set up CGHS dispensaries in different parts of Delhi at its own: and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Yes, Sir. Requests for opening of more dispensaries under CGHS in Delhi have been received for areas such as Subroto Park, Bahadurgarh, Ghaziabad, Dr. R.M.L. Hospital, Pitampura, Inderpuri Colony (Ghaziabad), Shakur Basti etc.

(c) to (e) Depending on the availability of resources and keeping in view relevant criteria, such as request from different Residential Welfare Associations, CGHS norms of certain minimum concentration of Central Government servants and pensioners in a particular locality etc., Government is gradually intensifying its net work of dispensaries in Delhi.

**Nomination of some more doctors in**

**एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे के रूप में अदा की गई राशि**

2953. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इण्डिया एवं इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों को दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप उन्हें मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा और इन विमानों के नष्ट होने के कारण उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(ख) दोनों विमान कंपनियों को बीमे की कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी राशि प्राप्त होनी शेष है; और

(ग) 31 जुलाई, 1996 तक दावा प्राधिकरणों एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठों में लम्बित पड़े दावों का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहिम):** (क) और (ख) एयर इण्डिया द्वारा किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था चूंकि 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान एअर इंडिया के विमानों की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उसी समयावधि के दौरान विमान दुर्घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 230.90 लाख रु का भुगतान किया गया था।

इंडियन एयरलाइन्स को विमानों के नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई चूंकि इसका विमान-बेड़ा पूरी तरह बीमाकृत है और कंपनी को बीमा कंपनियों द्वारा पूर्णत: क्षतिपूर्ति की जाती है। कंपनी ने 1992-93 से 1995-96 की समयावधि के दौरान बीमा कंपनियों से 202.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की।

(ग) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों तथा उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठों में क्षतिपूर्ति दावे के 55 मामले लंबित हैं।

**Expert Committee on Tobacco**

2954. SHRIV. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether some more doctors will be